

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या-157/2024

अन्तर्गत

अपील संख्या-60/2020

कैलाश चन्द्र गुप्ता

-प्रार्थी-अपीलार्थी

## बनाम

1. श्रीमती शुभ्रा सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी, निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
3. डॉ. निर्मल चौधरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।

-अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.11.2024

## उपस्थित :-

प्रार्थी-अपीलार्थी की ओर से : स्वयं अपीलार्थी  
अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या-60/2020 में अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 29.11.2023 पारित किया गया था, जिसमें निम्न प्रकार से प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये गये थे :-

“उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि यदि अपीलार्थी का नियमानुसार वेतन निर्धारण नहीं किया गया है तो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी वेतन आयोग के अनुसार अपीलार्थी का नियमानुसार वेतन निर्धारण किया जावे और सेवानिवृत्ति पश्चात् यदि अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति फायदों का भुगतान विलम्ब से किया गया है तो उक्त प्रावधानानुसार/नियमानुसार अपीलार्थी को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान भी किया जावे। उक्त निर्देशों की पालना इस आदेश के जारी होने की दिनांक से तीन माह में सुनिश्चित की जावे।”

2. इसके पश्चात पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अधिकरण ने पूर्व में पारित आदेश को पुर्नविलोकन कर आदेश दिनांक 29.01.2024 पारित किया गया था, जिसका प्रभावी भाग (Operating Part) निम्न प्रकार से हैं :-

“प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अधिकरण के समक्ष अपील संख्या 60/2020 दिनांक 08.01.2020 को प्रस्तुत की गई, जिस पर अधिकरण द्वारा अपील स्वीकार की जाकर दिनांक 29.11.2023 को आदेश पारित किया गया, में संशोधन करते हुए हम अप्रार्थी/प्रत्यर्थी विभाग को यह भी आदेश देना समीचीन समझते हैं कि विभाग द्वारा जो प्रार्थी/अपीलार्थी का वेतन निर्धारण किया गया उसकी शेष राशि एवं उस पर नियमानुसार 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्रार्थी/अपीलार्थी को भुगतान किया जावे तथा उसकी सेवा अवधि की सही गणना करते हुए चयनित वेतनमान का लाभ भी प्रदान किया जावे।”

3. प्रार्थी-अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह अभिकथन किया है कि अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने अधिकरण के आदेश दिनांक 29.11.2023 व 29.01.2024 की पालना आदिनांक तक नहीं की है। प्रत्यर्थीगण को नोटिस प्रेषित किये जाने के उपरान्त भी प्रत्यर्थी विभाग की ओर से कोई उपस्थिति नहीं दे रहा है।
4. प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 29.11.2023 एवं उसके पश्चात पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 29.01.2024 की पालना अभी तक नहीं की जा रही है। अतः बिना उचित कारण के जानबूझ कर अधिकरण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। प्रत्यर्थीगण जानबूझ कर अधिकरण के आदेश की पालना नहीं कर रहा है। इसलिए प्रत्यर्थी विभाग माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के दोषी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि प्रत्यर्थी विभाग से माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 29.11.2023 व 29.01.2024 की पालना करवायी जावे और पालना नहीं करने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के विरुद्ध अवमानना कार्यवाही प्रारम्भ कर माननीय उच्च न्यायालय को दण्ड हेतु रैफर किया जावे।
5. अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण की ओर से इस अवमानना याचिका का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।
6. हमने अपीलार्थी की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी-अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अवमानना प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। हम पाते हैं कि अधिकरण द्वारा पारित आदेशों की पालना अभी तक नहीं की गयी है। अधिकरण का आदेश पारित हुए करीब 10 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु अधिकरण के आदेशों की पालना नहीं की गयी है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधिकरण के आदेश के संबंध में कोई स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसे में प्रत्यर्थी

विभाग द्वारा अधिकरण के आदेशों की पालना न कर लगातार अवमानना की जा रही है।

7. यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अधिकरण ने प्रार्थी-अपीलार्थी की पूर्वोक्त अपील में आदेश पारित कर अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण को कार्यवाही करने का निर्देश दिया था। अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश की पालना अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने अभी तक नहीं की है। अतः अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के लिये यह आवश्यक था कि वे अधिकरण के आदेश की समयावधि में पालना करते या माननीय उच्च न्यायालय से इसकी क्रियान्विति पर कोई स्थगन आदेश प्राप्त करते। प्रिवी काउन्सिल के सर लॉरेन्स जेनकिन्स ने जसकर्ण बोइद बनाम पिरथीचन्द लाल (ए.आई.आर. 1918 पी.सी. 151) के प्रकरण में निम्न प्रकार अवधारित किया था :-

*"whatever be the theory under other systems of law, under the Indian law and procedure an original decree is not suspended by the presentation of an appeal nor is its operation interrupted where the decree on appeal is merely one of dismissal. There is nothing in the Indian law to warrant the suggestion that the decree or order of the court or tribunal of the first instance becomes final only on the termination of all proceedings by way of appeal or revision."*

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद नूह (ए.आई. आर. 1958 एस.सी. 86) में प्रिवी काउन्सिल के पूर्वोक्त निर्णय का अनुमोदन करते हुए निम्न मत व्यक्त किया था :-

*"the filing of an appeal might put the decree or order in jeopardy but until it is reversed or modified it remains effective."*

9. इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति पी.डी.देसाई ने हंसराज धीर के प्रकरण (1985 Cri. L.J. 1030) में अवमानना प्रकरण के सिद्धान्तों की निम्न प्रकार व्याख्या की थी :-

*"Once a case is decided, it is the bounden duty of the State and its subordinates to implement, with the utmost expedition, the said decision. In a Government which is ruled by law, there must be complete awareness to carry out faithfully and honestly the decisions rendered by courts of law after effective adjudication. Then only will private individuals, organisations and institutions learn to respect the decisions of courts. In absence of such attitude on the part of all concerned, chaotic conditions might arise and the functions assigned to the courts of law under the Constitution might be rendered a futile exercise. It requires to be emphasised, in this connection, that mere preferment of an appeal does not automatically operate as a stay of the decision under appeal and that till an application for stay is moved and granted by the appellate court, or, in the alternative, the court which rendered the decision is moved and grants an interim stay of the decision pending the*

*preferment of an appeal and grant of stay by the appellate court, the decision continues to be operative. Indeed, non-compliance with the decision on the mere ground that an appeal is contemplated to be preferred or is actually preferred, and that, therefore, the matter is subjudice, may amount to contempt of court punishable under the Contempt of Courts Act, 1971."*

10. उपर्युक्त विनिश्चयों के आलोक में और प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे विनम्र मतानुसार यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण ने इस अधिकरण के आदेश दिनांक 29.11.2023 व 29.01.2024 की पालना न कर उक्त न्यायिक आदेश की अवमानना कारित की है। हम इस अवमानना प्रकरण को अधिकरण में लम्बित रखना उचित नहीं समझते हैं और इस प्रकरण को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को Contempt of Courts Act, 1971 की धारा 10 के प्रावधान के क्रम में उपर्युक्त अवमानना कृत्य के लिए अवमाननाकर्ताओं के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु संदर्भित करना उचित समझते हैं।
11. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी-अपीलार्थी के अवमानना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अधिकरण के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए जाते हैं कि वे अप्रार्थीगण-प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 10 के अन्तर्गत अवमानना की कार्यवाही संस्थित करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ, जयपुर को संदर्भित करावें।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)